International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कैशलेस अर्थव्यवस्था का भारत पर प्रभाव

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

यह लेख भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाने का प्रयास करता है। मानव, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सही समन्वय और व्यावहारिक उपयोग किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक सभी पहलुओं को प्रभावित और निर्धारित करता है, लेकिन इसका राष्ट्र के आर्थिक पक्ष यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, तो हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार एक प्रगतिशील, गतिशील और गतिशील अर्थव्यवस्था रही है। जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह नगण्य होता है और सभी लेनदेन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट-आरटीजीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे भुगतान चैनल, इस स्थिति को कैशलेस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। "कैशलेस इकोनॉमी" शब्द का इस्तेमाल हर किसी के द्वारा उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था के अंदर नकदी प्रवाह नहीं होता है। सभी लेनदेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उपयोग किया जाता है। कैशलेस होने से चीजें आसान हो जाती हैं। यह लेनदेन की औपचारिकता में भी सहायता करता है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी मदद करता है। इसके अलावा, काले धन के प्रवाह से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इस लेख का उद्देश्य यह जांचना है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था का सार क्या है और यह भारत में लोगों को कैसे प्रभावित करता है।

मूल शब्द: कैशलेस अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, ज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

जब किसी अर्थव्यवस्था में लेन-देन भारी मात्रा में नोटों, सिक्कों या किसी अन्य भौतिक रूप पर आधारित नहीं होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड भुगतान साधनों के उपयोग से सहायता प्राप्त होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल के साथ बढ़ाया गया है। यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से एक प्रमुख कार्यक्रम है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अगर हम भारत को सही मायने में कैशलेस बनाना चाहते हैं, तो अब हमें विभिन्न चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है और ऑनलाइन माध्यम से लेनदेन करने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में लोगों को नकदी की कमी के कारण विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को सही मायने में कैशलेस बनाने के लिए, देश भर में सुविधाओं के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीकों की मदद से नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के कई फायदे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन के कारण लोगों को बैंकों में कैश रखना पड़ता है और इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गई है। साथ ही काले धन के प्रवाह पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों को उधार देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अधिक पैसा उपलब्ध है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि यह स्थिति लोगों को अपने करों का पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगी और इस प्रकार सरकार के पास जनता के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए अधिक पैसा होगा।

1991 में, भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IDF) की मदद से आर्थिक सुधार संरचनात्मक समायोजन सुविधा (ITH) कार्यक्रम शुरू किया। इस संरचनात्मक समायोजन सुविधा कार्यक्रम के तहत, भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लागू किया। उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत की बैंकिंग प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाए। एक ओर इसने बैंकिंग प्रणाली में व्यावसायिकता और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ। वहीं, ग्राहक की सुविधा का भी विस्तार हुआ। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड ने स्थानान्तरण को प्रोत्साहित किया और कभी-कभी नकद लेनदेन में चला गया। नेट बैंकिंग की शुरुआत के बाद, नकद हस्तांतरण के बजाय ऑनलाइन हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया गया। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रसार और इसके व्यापक प्रभाव के साथ, कैशलेस लेनदेन को सुलभ बनाया गया और भारत एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गया।

कैशलेस में न केवल एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर शामिल है, बल्कि अब पेटीएम, एयरटेल मनी, रिलायंस जियो, जैसे ई-अकाउंट्स भी शुरू हो गए हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भीम नाम का एक ऐसा ही ऐप शुरू किया गया है। इन सबके साथ आप अपनी छोटी से छोटी जरूरत को भी बिना नकद भुगतान किए खरीद सकते हैं। आज शहर की हर गली में मोबाइल रिचार्ज की दुकान से लेकर बुक स्टॉल और सब्जी विक्रेता, पेटीएम या एयरटेल पैसे रख कर आपको कैशलेस सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था और सरकार की पहल

कैशलेस अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के भीतर नकदी का प्रवाह न के बराबर होता है और सभी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। डिजिटल लेनदेन बेहतर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही लाते हैं। यह व्यक्ति को जब चाहे और जहां चाहे लेन-देन करने की स्वतंत्रता देता है। इस पहल ने न केवल तेजी से लेनदेन में मदद की है बल्कि साथ ही इसने देश में बहुत समय और पैसा बचाया है। सरकार भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सॉफ्टवेयर और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि प्रत्येक नागरिक को एक उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण की सफलता सुनिश्चित हो सके। कैशलेस लेनदेन से पैसे और समय की बचत होती है।

कैशलेस सोसाइटी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक सार्वभौमिक भुगतान इंटरफ़ेस स्थापित किया है। भुगतान सेवा प्रदाता, अंतर्निहित खाते प्रदान करने वाले बैंक, और नेशनल पेमेंट्स कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट (एनपीसीआई), जो तेजी से भुगतान सेवाओं के माध्यम से लेनदेन को प्रभावित करने वाले वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रिज़ॉल्यूशन का आश्वासन देकर केंद्रीय स्विच के रूप में कार्य करता है, तीन आवश्यक हितधारक हैं।

इस तरह भारत एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत में इसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक है। बहुत ही छोटी यात्रा में उच्च वर्ग के साथ-साथ शिक्षित मध्यम वर्ग ही ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाता है। लेकिन 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण कर दिया गया था, नकदी की कमी के कारण इस कैशलेस अर्थव्यवस्था के महत्व को आम लोग भी समझ गए थे। आम लोग भी कैशलेस अर्थव्यवस्था के महत्व और महत्व के बारे में जागरूक हुए और भारत सरकार ने भी निरंतर संचार के माध्यम से इसे बढ़ावा देने का फैसला किया।

कैशलेस इकोनॉमी का एक फायदा यह भी होगा कि काले धन की समस्या पर अंकुश लगेगा। काले धन का एक बड़ा हिस्सा नकद संग्रह के रूप में है, जब कैशलेस व्यवस्था होगी, तो न तो नकदी का संग्रह होगा और न ही काले धन का संचय होगा। साथ ही कैशलेस सिस्टम के जरिए लेन-देन और ऑनलाइन रिकॉर्ड में पारदर्शिता से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

कैशलेस प्रणाली के उदय के साथ, कर आधार का विस्तार होगा। आम नागरिकों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा कि टैक्स की दर कम हो जाएगी। कर आधार में वृद्धि और कर संग्रह में वृद्धि के साथ, सरकार आम जनता के कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित करने में सक्षम होगी, परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार और गुणवत्ता के कारण, भारत के बड़े पैमाने पर जनसंख्या, भारत की बड़ी माल पूंजी का निर्माण होगा जो देश के विकास को गति देगा।

क्या भारत वास्तव में कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए तैयार है?

इस तरह भारत में कैशलेस प्रणाली की बहुत उपयोगिता है, लेकिन इस प्रणाली को बढ़ाने और विकसित करने में भारत में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहले, भारत में नेट बैंकिंग से संबंधित बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। भारत के ऑनलाइन बाजार और इसके उपभोक्ताओं के बीच अनुपात का असंतुलन भी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

एक बड़ी कठिनाई है। केवल 27% भारतीय आबादी अभी भी इंटरनेट उपयोगकर्ता है। ऐसी स्थिति में जहां इंटरनेट कैशलेस प्रणाली का आधार है, भारत में यह प्रणाली बहुसंख्यक आबादी से दूर है। इसके अलावा हैकिंग और साइबर क्राइम जैसे अपराध भी इस व्यवस्था के प्रसार में बाधक होंगे।

हालांकि भारत में कैशलेस व्यवस्था संभव नहीं है लेकिन जिस तरह से तकनीक विकसित हुई है। मध्यम वर्ग उभरा है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत में कैशलेस की जगह इंटीग्रेटेड सिस्टम की स्वीकार्यता बढ़ी है। यह बहुत अच्छी बात है कि चकबंदी शिक्षा का प्रभाव न केवल भारतीय शहरों में बढ़ा है, बल्कि आज हर गाँव में भी इसका प्रभाव बढ़ गया है। इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में प्रगति को अपना रहा है, जो स्वागत योग्य है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ

भारत में कैशलेस समाज का मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड काली अर्थव्यवस्थाओं या भूमिगत बाजारों को बनाए रखना लगभग असंभव बना देता है जो अक्सर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए हानिकारक साबित होते हैं। इससे सिस्टम में काले धन के प्रवेश की संभावना कम हो जाती है। आपराधिक लेनदेन करना भी बहुत जोखिम भरा है। एक अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक नकदी पर आधारित है, एक बड़े पैमाने पर भूमिगत बाजार की सुविधा प्रदान करती है जो मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। कैशलेस लेनदेन से ऐसी नापाक गतिविधियों के लिए धन का शोधन करना मुश्किल हो जाता है।

- **कर चोरी पर रोक:**

अगर अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाती है, तो कर चोरी की घटनाओं में काफी कमी आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कैशलेस लेनदेन का सबूत डेटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय से संबंधित डेटा एकत्र करना आसान हो जाता है।

- **काले धन पर प्रतिबंध:**

कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए आर्थिक लेनदेन से काले धन के बाजार को खत्म किया जा सकता है। नकद आधारित अर्थव्यवस्था से काला धन एकत्र करना, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान हो जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था इनसे छुटकारा पाने में मददगार साबित होगी।

- **बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच:**

यह प्रयास सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रणाली में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के बजाय सिर्फ एक डिजिटल ढांचे की जरूरत होगी।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- **लागत में कमी:**

बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष स्थान पर पहुंचने की शर्त को हटा दिया जाएगा, जिससे लेन-देन के मूल्य के साथ-साथ परिवहन लागत भी कम हो जाएगी। अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ता है तो रिजर्व बैंक को कम नोट छापने पड़ेंगे, जिससे नोटों की छपाई की भारी लागत कम हो सकती है। साथ ही एटीएम को सुचारू रूप से चलाने में बैंकों का खर्चा भी कम होगा।

- **जनकल्याणकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ाना:**

जनता के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि बिचौलियों के हाथ में जाने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचेगा।

कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह में चुनौतियां

एक कैशलेस सोसायटी अपने नियमों, विनियमों, शर्तों और नियंत्रणों के अपने सेट के साथ आएगी। भारत में विशेष रूप से, विश्व बैंक के अनुसार, लगभग सवा अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक खाते भी नहीं हैं। यह कमी हाशिए पर है, और इस संबंध में, वित्तीय समावेशन के लिए एक डिजिटल क्रांति के लिए अग्रणी निश्चित रूप से एक कदम आगे है। इसके अलावा, भारत में इंटरनेट की पहुंच कम है, और यह महंगा भी है। ग्रामीण और गरीबों को इस कदम को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई ठोस बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है।

- **नेट बैंकिंग से बाहर अधिकांश आबादी:**

वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बचत के संबंध में पूरे देश में केवल 46 प्रतिशत लोगों की ही बैंकिंग गतिविधियों तक पहुंच है। जन धन योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए, लेकिन अधिकांश खातों में कोई लेन-देन नहीं हो रहा था। कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी है कि इन खातों को क्रियाशील बनाया जाए, यानी इनसे कुछ लेन-देन होना चाहिए।

- **असंगठित क्षेत्र का प्रभाव:**

अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग के दायरे में आता है तो भी कैशलेस होने का अभियान शायद ही सफल हो, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए अभिशप्त है। यहां होने वाले ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में ही होते हैं। ऐसे में किसी से यह अपेक्षा करना बेईमानी होगी कि वह अपने बैंक खाते में नकद में प्राप्त वेतन जमा करेगा और फिर कार्ड या मोबाइल वॉलेट का उपयोग करेगा।

- **साइबर सुरक्षा मुद्दा:**

गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में 30 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो गए थे और यह हमारी कमजोर साइबर सुरक्षा का एक उदाहरण है। आज देशों के बीच साइबर युद्ध चल रहा है और भारत में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में अगर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाती है तो हमें अपनी साइबर सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा।

- **नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट लागत:**

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता या विफलता भारत में आम है। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की कीमत अभी भी बहुत अधिक है। कार्ड पर शुल्क, ऑनलाइन लेनदेन विक्रेताओं द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हैं। भारत में डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) बहुत अधिक है। लोगों के बीच कंप्यूटर साक्षरता अभी भी कम है। इसके अलावा लोग लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल करने को लेकर आशंकित हैं।

निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील देश में जहां बुनियादी सुविधाएं अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश आबादी ग्रामीण है और लगभग एक प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। वहां इतनी जल्दी कैशलेस अर्थव्यवस्था की कल्पना करना संभव नहीं है। हमें पहले आधार बनाना होगा और फिर लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। साथ ही हमारे जैसे देश में केवल कैशलेस से ही समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, हमें और भी कई कदम उठाने पड़ते हैं, कैशलेस उनका ही एक हिस्सा है।

विमुद्रीकरण के बाद, लोगों ने अंततः क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य चैनलों के रूप में प्लास्टिक की मुद्रा में विश्वास करना शुरू कर दिया है। पर्याप्त नकदी की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन बैंकिंग बाजार को प्रमुखता मिली है। इसके अलावा, भुगतान करने के लिए ई-कॉमर्स माध्यम भी लोकप्रिय हो गया है और अधिकांश लोग अब डिजिटल माध्यमों की मदद से पचास रुपये भी दे रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों को अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के लिए अच्छा माना जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह कठिन है लेकिन सरकार भीम ऐप, लकी ग्राहक योजना, डिजी बैंक योजना, जन धन योजना आदि जैसे कई उपाय भी कर रही है। कैशलेस इंडिया एक ऐसा विचार है जो व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए उपयुक्त समय पर आया है। लेकिन, इसके लिए कारगर उपाय करने होंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतिशील और विकासशील बनाया जा सके।

References

- Al-Dalaien, B. O. A. (2017). Cashless economy in India: challenges ahead. *Asian Journal of Applied Science and Technology*, *1*(7), 168-174.
- Al-Dalaien, B. O. A. (2017). Cashless economy in India: challenges ahead. *Asian Journal of Applied Science and Technology*, *1*(7), 168-174.
- Balaji, K. C., & Balaji, K. (2017). A study on demonetization and its impact on cashless transactions. *International Journal of Advanced Scientific Research & Development*, *4*(3), 58-64.

- Chaudhari, T. (2017). The critical analysis of cashless transaction. *International Journal of Commerce and Management Research*, *3*(3), 92-94.
- Jain, P. (2017). Cashless system of colleges in India. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, *1*(3), 1-7.
- Kamboh, K. M., & Leghari, M. E. J. (2016). Impact of cashless banking on profitability: A case study of banking industry of Pakistan. *Paradigms*, *10*(2), 82.
- Kumar, A. (2017). Demonetization and cashless banking transactions in India. *International Journal of New Innovations in Engineering and Technology*, *7*(3), 30-36.
- Mahajan, P., & Singla, A. (2017). Effect of demonetization on financial inclusion in India. *International Journal of Science Technology and Management*, *6*(1), 338-343.
- Mukhopadhyay, B. (2016). Understanding cashless payments in India. *Financial Innovation*, *2*(1), 1-26.
- Nagdev, K., Kumar, P., Rajesh, A., & Kumar, S. (2018). Measuring demonetisation: a path towards the cashless India. *International Journal of Public Sector Performance Management*, *4*(1), 114-132.